

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज एवं ग्रा0 अभि0से0अनुभाग-2

देहरादून:: दिनांक: 07 जनवरी, 2011

विषय:- प्रथम अनुपूरक माँग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 1207/ग्रा0अभि0से0/लेखा-दो-01/30 - बजट/2010-11 दिनांक 01 नवम्बर, 2010 के क्रम में शासनादेश संख्या 542/XXVII (1)/2010 दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 एवं शासनादेश संख्या 369/XII/2010/83 (04)/2009-TC दिनांक 05 अगस्त, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुश्रवण परिषद की स्थापना हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष की बचनबद्ध/अबचनबद्ध मदों में निम्नवत कुल रुपये 10,00,000.00 (रुपये दस लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्य पाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	लेखाशीर्षक	धनराशि (हजार रुपये में)	
	2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम- आयोजनागत 800- अन्य व्यय 09- ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुश्रवण परिषद की स्थापना	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-11	
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1.	01- वेतन	70	—
2.	04- यात्रा व्यय	50	—
3.	06- अन्य भत्ते	50	—
4.	08- कार्यालय व्यय	30	—
5.	09- विद्युत देय	20	—
6.	10- जलकर/जलप्रभार	05	—
7.	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15	—
8.	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	—
9.	13-टेलीफोन पर व्यय	40	—
10.	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	355	—

11.	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	150	—
12.	17- किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	105	—
13.	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10	—
	योग-	1000	—

(रुपये दस लाख मात्र)

2. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 369/XII/2010/83(04)/2009-TC दिनांक 05 अगस्त, 2010 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, तथा एक मद की धनराशि दूसरी मद में कदापि व्यय न की जाय।

3. प्रश्नगत धनराशि की फॉट कर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों पर रखा जाना सुनिश्चित करें तथा दौहरे आहरण के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-19 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-09-ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुश्रवण परिषद की स्थापना की मानक पदों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या: 309(P)/XXVII(4)/2010, दिनांक 05 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)

सचिव।

संख्या: 06 (1)/XII/2011/87(04)/2009-TC तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (ए एण्ड ई) ओबराय भवन सहारनपुर रोड़ माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार वैभव पैलेस सी-1/105 इन्दिरा नगर देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशकोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर० पी० फुलोरिया)

संयुक्त सचिव।

02/01/11